



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]
No. 537]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2005/ज्यैष्ठ 10, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2005/JYAISTHA 10, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

सं. 5(आर ई-2005)/2004—2009

का.आ. 740(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. पैराग्राफ 4.1.3 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

अग्रिम लाइसेंस	4.1.3	अग्रिम लाइसेंस, निवेशों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हेतु जारी किया जाता है जिन्हें निर्यात उत्पाद में वास्तविक तौर पर शामिल किया जाता है (अपशिष्ट हेतु सामान्य अनुमति देते हुए)। इसके अलावा, इंधन, तेल, ऊर्जा, कैटलिस्ट आदि, जिन्हें निर्यात उत्पाद प्राप्त करने हेतु प्रयोग में खपत/प्रयुक्त किया जाता है, को भी स्कीम के तहत अनुमत किया जाता है। तथापि, महानिदेशक, विदेश व्यापार, लोकहित में, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से किसी उत्पाद अथवा उत्पादों को अग्रिम लाइसेंस की सीमा से बाहर रख सकते हैं।
----------------	-------	---

	<p>लाइसेंस की बीमा लागत भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक अनिवार्य स्पेयरस का शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति है जिन्हें अग्रिम लाइसेंस के तहत भी परिणामी उत्पाद के साथ निर्यातित/आपूर्तित करना आवश्यक है।</p> <p>सियोन के तहत उल्लिखित निर्यात मर्दों और निवेशों के आधार पर अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.7 के तहत स्वघोषित मानदण्डों अथवा तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी उन्हें जारी किया जा सकता है। अग्रिम लाइसेंस, सहायक विनिर्माता से जुड़े व्यापारी निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक को जारी किया जा सकता है।</p> <p>(i) वास्तविक निर्यातों हेतु (एसईजैड को किए निर्यातों सहित); और/अथवा</p> <p>(ii) अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु; और/अथवा</p> <p>(iii) नीति के पैराग्राफ 8.2 (ख), (ग), (घ), (ङ.), (च), (छ), (झ) और (ज) में उल्लिखित वर्गों को माल की आपूर्ति हेतु मुख्य ठेकेदार को;</p> <p>माल के विनिर्माण में आवश्यक निवेशों के आयात हेतु।</p> <p>इसके अलावा, नीति के पैरा 8.2 (घ), (ङ.), (च), (छ) और (ज) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के संबंध में ऐसी परियोजना के मुख्य ठेकेदार के उप-ठेकेदार द्वारा अग्रिम लाइसेंस का लाभ उठाया जा सकता है बशर्ते कि उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो।</p> <p>ऐसा लाइसेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्यक्रम के तहत अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को की जाने वाली आपूर्तियों तथा मुक्त विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतान हेतु जारी किया जा सकता है।</p>
--	---

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/00081/एएम 99/पीसी-IV]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

No. 5(RE-2005)/2004—2009

S.O. 740(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments :

1. Paragraph 4.1.3 is amended to read as under:

Advance Licence	4.1.3	<p>An Advance Licence is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts etc. which are consumed/utilised in the course of their use to obtain the export product, may also be allowed under the scheme. However the Director General of Foreign Trade, by means of a Public Notice, may in public interest exclude any product or products from the purview of Advance Licence.</p> <p>Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the licence which are required to be exported/ supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Licence.</p> <p>Advance Licences are issued on the basis of the inputs and export items given under SION. However, they can also be issued on the basis of Adhoc norms or self declared norms as per para 4.7 of Handbook (Vo.I). Advance Licence can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s):</p> <p>i) for Physical exports (including exports to SEZ); and/ or</p> <p>ii) for Intermediate supplies; and /or</p> <p>iii) to the main contractor for supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j)</p>
-----------------	-------	--

	<p>of the Policy;</p> <p>for import of inputs required in the manufacture of goods.</p> <p>In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of the Policy, an Advance Licence can also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub contractor(s) appears in the main contract.</p> <p>Such licence can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.</p>
--	---

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/00081/AM99/PC. IV]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.